

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र : भावी वृद्धि की शुरुआत करने में इसकी भूमिका*

आर. गांधी

देवियों और सज्जनों को नमस्कार।

2. कोलकाता में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) की इस महत्त्वपूर्ण बैठक में शामिल होना सम्मान और सौभाग्य -दोनों की बात है। 1920 के दशक में छोटी शुरुआत करके आईसीसी ने लंबा रस्ता तय किया है और वर्तमान में यह अग्रणी राष्ट्रीय चेंबर के रूप में विकसित हो चुका है जिसका संचालन कोलकाता से हो रहा है। बैंक वित्तीय प्रणाली के मुख्य आधार हैं इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श में नए परिवेश में बैंकों की भूमिका के पुनर्व्यवस्थित होने में के बारे सभी प्रतिभागियों को महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई होगी। सम्मेलन में प्रतिभागियों का बढ़िया मिश्रण है जिसमें न सिर्फ सरकार एवं प्रमुख वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं बल्कि लेखा-परीक्षा करने वाली फर्मों के लोग और सामान्य श्रोता भी इसमें शामिल हैं। मुझे यकीन है कि इस विविध प्रतिनिधित्व ने विचार-विमर्श किए जाने वाले प्रत्येक मामले में अलग-अलग दृष्टिकोण तथा संभावित समाधान प्रस्तुत किया होगा।

वित्तीय क्षेत्र एवं आर्थिक वृद्धि

3. बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य निष्क्रिय बचत को जुटाकर लाभकारी निवेश के लिए ऋण प्रदान करना है। वित्तीय क्षेत्र एवं वास्तविक क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि के बीच संबंध के अध्ययन के लिए बहुत से अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। आर्थिक वृद्धि के पुराने मॉडल, जिसमें इसे भूमि पर आधारित अर्थात् पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिकी तथा उद्यमिता से संबंधित माना जाता था, में संशोधन किया गया है। आर्थिक वृद्धि का नया प्रतिमान बचत दर, निवेश

* 14 जून 2014 को ताज बंगाल कोलकाता में आयोजित आईसीसी बैंकिंग के छठवे शिखर सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी का समापन भाषण। सुश्री रेखा मिश्रा, निदेशक, श्री सैबल घोष, सहायक परामर्शदाता एवं श्री राधेश्याम वर्मा, अनुसंधान अधिकारी से मिले सहयोग के लिए आभार।

पर प्रतिफल एवं मध्यस्थता की लागत पर आधारित होता है। हम इन तीनों कारकों के संबंध में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका और महत्त्व को सरलतापूर्वक देख सकते हैं। अतः मात्रा, गुणवत्ता अर्थात् उत्पादकता एवं पूंजी की दक्षता पर वित्त का महत्त्वपूर्ण असर होने के बारे में सर्वसम्मति होने के बावजूद निर्णायक मंडल अभी भी यह निर्णय नहीं ले पाया है कि आर्थिक वृद्धि में बैंकों की भूमिका अधिक है या पूंजी बाजार की। अनुसंधान के विचार तथा परिणाम भी उतने ही विभक्त हैं। वृद्धि को प्रारंभ करने में पूंजी बाजार की भूमिका को साबित करने के लिए बहुधा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम का उदाहरण दिया जाता है। इसके विरोध में, यह कहने के लिए कि बैंक वृद्धि की शुरुआत करते हैं, जर्मनी और जापान का उदाहरण दिया जाता है।

4. बैंक राष्ट्र की वित्तीय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी तैयार करते हैं जो चलनिधि, परिपक्वता तथा जोखिम रूपांतरण के माध्यम से बहुत से कार्य करते हैं। सचमुच इस बात के खंडन की आवश्यकता नहीं है कि अर्थव्यवस्था की सेहत एक प्रकार से बैंकिंग प्रणाली का ही प्रतिबिंब होती है, विशेषरूप से हमारे जैसी बैंक-आधारित वित्तीय प्रणालियों में। बेशक, इसके विपरीत बात भी उतनी ही सत्य है। मुझे वह बात याद आती है कि बैंक मानव शरीर के हृदय के समान है और वह जो पूंजी उपलब्ध कराता है वह शरीर में रक्त के समान होता है। जब तक रक्त निर्बाधरूप से बहता रहेगा, अंग (हृदय) मजबूत और स्वस्थ बना रहेगा। हालांकि, किसी भी कारण से किसी अंग को रक्त प्रवाह मिलना बंद हो जाए तो वह हिस्सा बेकार हो जाएगा। इसलिए यह किसी आश्चर्य की बात नहीं है कि रिजर्व बैंक हमेशा जानबूझकर पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध कराने और अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने की कोशिश करता है।

भारतीय अनुभव

5. भारत में बैंकों और पूंजी बाजार -दोनों का पुराना इतिहास रहा है। भारत के आर्थिक इतिहास में बताया गया है कि किस प्रकार से बहुत से शहरों में दोनों बहुत सक्रिय रहे हैं, हालांकि मुंबई का अन्य सभी पर प्रभुत्व रहा है। बैंकिंग क्षेत्र धीमे और अधिक मजबूती से, विशेषरूप से विगत लगभग पच्चीस वर्षों में हुए वित्तीय क्षेत्र में

हुए सुधारों के बाद, निवेश के लिए निधीकरण के स्रोत के रूप में उभरा है।

6. भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश की व्यवस्था करने में बैंकों का वास्तविक योगदान क्या रहा है? मार्च 1951 के अंत में बैंक ऋण ₹5 बिलियन था जो बढ़कर मार्च 1961 तक ₹13 बिलियन, मार्च 1971 तक ₹47 बिलियन, मार्च 1981 तक ₹254 बिलियन, मार्च 1991 तक ₹1164 बिलियन, मार्च 2001 तक ₹5114 बिलियन, मार्च 2011 तक ₹39420 बिलियन और मार्च 2013 तक ₹52604 बिलियन हो गया। इन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार का क्या योगदान रहा है ? 1970 के दशक में जहां पूंजी बाजार ने ₹10 बिलियन मूल्य के इक्विटी, बांड एवं डिबेंचर जुटाने में मदद की वहीं उस अवधि में बैंकों ने ₹207 बिलियन मूल्य का ऋण प्रदान किया। 1980 के दशक में समरूप आंकड़े ₹233 बिलियन एवं ₹910 बिलियन रहे। 1990 के दशक में ये क्रमशः ₹1172 बिलियन और ₹3950 बिलियन रहे और 2000 के दशक में ये क्रमशः ₹2115 बिलियन तथा ₹34206 बिलियन रहे। वित्तीय वर्ष 2011 एवं 2012 में पूंजी बाजार का योगदान ₹318 बिलियन तथा बैंकों का योगदान ₹13,284 बिलियन रहा।

7. बैंक बांडों एवं डिबेंचरों में निवेश के माध्यम से निधि उपलब्ध कराते हैं। चूंकि यह निवेश कॉर्पोरेटों द्वारा जारी बांडों के स्थान पर प्रचुर मात्रा में सरकारी बांडों में किया जाता है। इनसे संबंधित वर्गीकरण अभी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मैंने यहां उनका समावेश नहीं किया है।

8. पूंजी बाजार के फ्रीके कार्यनिष्पादन पर हम विलाप कर सकते हैं, किंतु पिछले 20 वर्षों में निजी प्लेसमेंट मार्केट में हुई वृद्धि क्षतिपूर्ति करने वाला लक्षण रहा है। वहां पर निर्गम मुख्य रूप से बांडों एवं डिबेंचरों के रूप में होने के बावजूद आकार में हुई वृद्धि बहुत आश्वस्त करने वाली रही है। इसे 1990 के दशक के मध्य में लोकप्रियता प्राप्त हुई। 1995-96 से लेकर 2000-01 तक इस बाजार ने ₹752 बिलियन एकत्र किया और अगले 10 वर्षों में इसने ₹7614 बिलियन एकत्र करने में सहायता की। वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में इस बाजार ने ₹2,009 बिलियन एकत्र किया।

9. हम यह देख कर खुश हैं कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए बैंक इतनी बेहतरीन अंगरक्षक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, परंतु क्या हम बैंक वित्तीय पर मुख्यरूप से आश्रित होकर खुश रह पाएंगे? क्या बैंकों को हम बहुत अधिक जोखिम लेने को मजबूर कर रहे हैं और इस प्रकार से जमाकर्ताओं के पैसों को खतरे में डाल रहे हैं ?

10. भारतीय वित्तीय प्रणाली में बैंकों की प्रमुख भूमिका को देखते हुए तथा वास्तविक दृष्टिकोण को अपनाते हुए बैंकों से हमारी अपेक्षा है कि वे सभी प्रकार की निवेश आवश्यकताओं के लिए समग्र रूप से ऋण प्रदान करें ? बिना इन बातों को ध्यान में रखे कि चाहे वे अल्पावधि, मध्यावधि या दीर्घावधि हैं, या वे ऋण हैं, कर्ज हैं या इक्विटी वित्तीय हैं, या यह कि उसमें कम, मध्यम या अधिक जोखिम निहित है ? क्या हमें अपने बैंकों को जर्मनी के यूनिवर्सल बैंकों में परिवर्तित कर देना चाहिए जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सभी प्रकार की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ?

11. या विकल्प के रूप में हमें पूंजी बाजार का विकास करना चाहिए ताकि वह निवेश के साथ जोखिमपूर्ण निवेश की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके ? जैसा कि अमरीका में हो रहा है ?

12. हमें इन प्रश्नों पर विचार करने और रणनीतिक फैसले लेने की आवश्यकता है।

बारहवीं योजना

13. 12वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक समावेशी और संवहनीय वित्तीय वृद्धि को तेज गति से प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें यह नोट किया गया है कि आज की स्थिति में भारत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि बनाए रख सकता है। इसे 9 या 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए और अधिक निवेश स्रोतों को जुटाने, इन संसाधनों को अधिक दक्ष पूंजी बाजारों के माध्यम से बेहतर ढंग से वितरित करने, सरकारी एवं सरकारी-निजी सहभागिता (पीपीपी) -दोनों के माध्यम से आधारभूत संरचना के लिए अधिक निवेश करने एवं सरकारी संसाधनों का अधिक दक्षतापूर्वक प्रयोग करने की आवश्यकता होगी

14. बारहवीं योजना में 2012-17 के दौरान 8 प्रतिशत की वृद्धि दर को प्रारंभ के लिए निवेश की महत्वाकांक्षी योजना शामिल की गई है। इसमें ₹56 ट्रिलियन मूल्य के संसाधन जुटाने का लक्ष्य है। बारहवीं योजना की परिकल्पना के अनुसार आधारभूत संरचना के लिए केंद्र द्वारा ₹16 ट्रिलियन और राज्यों द्वारा ₹12.89 ट्रिलियन के कुल सरकारी निवेश का लक्ष्य है। शेष ₹26.83 ट्रिलियन की राशि निजी क्षेत्र के निवेश, जिसमें सरकारी-निजी सहभागिता (पीपीपी) परियोजनाएं भी शामिल हैं, के माध्यम से जुटाई जानी है जो कि बारहवीं योजना के दौरान अपेक्षित निवेश का 48.14 प्रतिशत है। यह ग्यारहवीं योजना के 36.61 प्रतिशत के प्रत्याशित लक्ष्य से काफी अधिक है। तदनुसार योजना का लक्ष्य बैंक वित्तीयन को प्रोत्साहित करने के साथ ही पूंजी बाजार, विशेषरूप से कर्ज बाजार, को विकसित करना है।

15. रिजर्व बैंक से होने के नाते मैं आने वाले वर्षों में बैंकों की भूमिका के बारे में और चिन्तन करना चाहूंगा।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

16. अग्रणी अर्थशास्त्री अक्सर वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सुधारों का बात करते हैं जिसके केंद्र में स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली होती है जो आर्थिक वृद्धि को सहारा प्रदान करती है। दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है जिसके पास विस्तृत वित्तीय प्रणाली है। विभिन्न प्रकार की बैंक और गैर-बैंक -दोनों तरह की वित्तीय संस्थाएँ इसकी विशेषताएं हैं। वित्तीय प्रणाली में बैंकों का प्रमुख योगदान है। सुधारों के बाद की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का औसतन लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा बैंक आस्तियां होती हैं। वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र में 26 सरकारी बैंक हैं जिनमें सरकार की इक्विटी धारित अधिक है, 20 निजी बैंक हैं जिनमें 7 नए (डी नोवो) (जिनहोंने 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद काम प्रारंभ किया) निजी बैंक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यह अंतर समाप्त कर दिया है और 40 से अधिक विदेशी बैंक यहां हैं जो शाखाओं के रूप में कार्य करते हैं।

17. 1991 में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की शुरुआत होने से पहले बहुत अधिक विनियामित और वित्तीयरूप से दमित होना भारतीय

वित्तीय प्रणाली की विशेषता थी। आरक्षित निधियों के उच्च स्तर को बनाए रखना, ब्याज दर नियंत्रण तथा पहले से निर्धारित क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के आबंटन ने बैंकों द्वारा संसाधन जुटाने और उनके आबंटन पर विपरीत असर डाला।

18. भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार की नींव 1992-97 की अवधि में रखी गई। सुधारों के पांच प्रमुख मुद्दे थे : सावधानीपूर्वक और समुचित क्रमनिर्धारण, परस्पर सहारा देने वाले उपाय, बैंकिंग सुधारों तथा संबंधित नीतियों (यथा, मौद्रिक, विदेशी इत्यादि) के पूरक, वित्तीय आधारभूत संरचना का विकास करना तथा विकासशील वित्तीय बाजारों की देखभाल करना। वित्तीय प्रणाली में किए गए प्रमुख सुधारों में अन्य के अलावा कुछ इस प्रकार थे - सांविधिक आरक्षित निधियों की अपेक्षाओं को कम करना, ब्याज दरों के प्रभुत्व वाले दौर को उदार बनाना, जमा पक्ष के स्थान पर उधार देने के पक्ष को प्राथमिकता देना, विदेशी बैंकों के प्रवेश में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने तथा नए (डी नोवो) निजी बैंकों की स्थापना को अनुमति प्रदान कर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, विवेकपूर्ण उपायों (पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं, आय की स्वीकृति, आस्तित्व वर्गीकरण तथा ऋणों के लिए प्रावधानीकरण के मानदंड, एक्सपोजर मानदंड, लेखांकन मानदंड) की स्थापना करना तथा बाजार अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए उनके वार्षिक लेखा-परीक्षित विवरणों में और अधिक प्रकटीकरण तथा पारदर्शिता के स्तरों को और बढ़ाना।

19. 1992 से प्रारंभ होकर 2013 तक की सुधार की अवधि के दौरान बैंकों की वास्तविक आस्तियों में लगभग 10 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई है। समान अवधि में जमाराशियों तथा ऋण -दोनों की वास्तविक वृद्धि दर क्रमशः लगभग 10 से 12 प्रतिशत रही है।

20. यह जानकर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज उन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाना है जो आगे चलकर बैंक उद्योग के भविष्य की दिशा को निर्धारित करने वाले हैं। मैं इस अवसर का लाभ लेते हुए इनमें से कुछ तथा अन्य संबंधित विषयों पर अपने विचार आप लोगों से साझा करना चाहूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ

कि आने वाले वर्षों में इनसे बैंक उद्योग की रूपरेखा निर्धारित होने वाली है।

आधारभूत संरचना का वित्तपोषण

21. मेरे दिमाग में तुरंत आ रहा पहला मुद्दा आधारभूत संरचना के वित्तपोषण का है। मुझे यकीन है कि यह मुद्दा आप लोगों के दिमाग में भी प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा होगा। आधारभूत संरचना के अपर्याप्त होने से अर्थव्यवस्था पर मंदीकारक असर पड़ता है, जिसका उत्पादकता, रोजगार, वैयक्तिक आय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और लागत पर नकारात्मक असर होता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए लगभग ₹.56 ट्रिलियन की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र की भूमिका धीरे-धीरे बढ़ रही है। सीमित राजकोषीय संसाधनों तथा इनके पूर्ण होने में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए दीर्घावधि के लिए निधि उपलब्ध कराने वालों को तैयार करने की आवश्यकता है।

क्या इसमें बैंक योगदान कर सकते हैं ? हां, और वस्तुतः बैंकों ने पहले ही ऐसा कर दिया है। पूंजी बाजार घट रहा है किंतु आधारभूत संरचना के लिए बैंकों द्वारा वित्तपोषण लगातार बढ़ा है। 1999-2000 में आधारभूत संरचना क्षेत्र पर बकाया बैंक ऋण ₹72 बिलियन था वह 2012-13 में बढ़कर ₹7,860 बिलियन हो गया है। इसकी समग्र वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) में 40 प्रतिशत से अधिक रही है जबकि समान अवधि के दौरान सभी उद्योगों को बैंकों द्वारा वित्तपोषण में समग्र सीएजीआर 20 प्रतिशत रहा है। हालांकि, इस प्रकार की वृद्धि तथा सामान्य आर्थिक मंदी और नीतिगत समस्याओं के कारण बैंकों पर संकेंद्रण जोखिम (बैंकिंग पुस्तिकाओं में आधारभूत संरचना का निधीयन 15 प्रतिशत तक के उच्च स्तर पर रहा है) उत्पन्न हो गया है। बड़े पैमाने पर जोखिमपूर्ण आस्तियां बैंकों के सिर पर मढ़ दी गई हैं। इसके अलावा, बैंकों की अल्पावधि निधियों को बहुत दीर्घावधि तक प्रयोग में लाए जाने की संरचनागत समस्या भी है। बैंकों ने 12 से 15 वर्षों की मध्यम अवधि के लिए निधीयन करने के रूप में बीच का एक रास्ता निकाला। इससे प्रारंभिक समस्याओं का समाधान तो निकल गया किंतु मूलभूतरूप से यह एक कमजोर व्यवस्था है तथा हाल की तनावपूर्ण अवधि के

दौरान इसकी कमजोरियां जाहिर हो गई हैं। बैंकों को उनकी आस्ति-देयता मिश्रणों को ध्यान में रखते हुए आधारभूत संरचनाओं को ऋण प्रदान करने के अपने-अपने कार्यक्रमों को समुचित ढंग से निर्धारित करना होगा, उनको दीर्घावधि संसाधनों को जुटाना भी पड़ सकता है। प्रतिपक्षी तथा अन्य जोखिमों से निपटने के लिए उनको दीर्घावधि नियत दर अथवा परिवर्तनशील दर वाले उत्पादों को विकसित करना चाहिए अथवा समुचित हैजिंग इंस्ट्रूमेंटों का विकास करना चाहिए। अंतरण वित्तपोषण (टेक आउट फाइनेंस) एक अन्य संभावित उपाय है। आधारभूत संरचना कर्ज निधि (आईडीएफ) भी ऐसा ही एक उपाय है। वर्तमान में यह पहल नवजात अवस्था में हैं किंतु इनमें दीर्घावधि उपाय निहित हैं।

22. दीर्घावधि में, आधारभूत संरचना के व्यवहार्य वित्तपोषण के लिए दक्ष एवं जीवंत कॉर्पोरेट बांड बाजार का होना सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अन्य क्षेत्रों के लिए दीर्घावधि निधियन उपलब्ध कराके पूंजी बाजार यह महती आवश्यकता वाला कर्ज उपलब्ध करा सकता है जो उधारकर्ताओं तथा निवेशकों -दोनों के लिए एक समान लाभकारी होगा। इसके कारण वित्तीय बाजारों का गहन एवं विस्तृत होना भी सुनिश्चित होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय क्षेत्र से संबंधित नीतियों के आधार स्तंभों में से एक है।

लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) का वित्तपोषण करना

23. दूसरा मुद्दा, मैं जिसका जिक्र करना चाहूंगा वह है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों अथवा एमएसएमई, जिस नाम से हम इन्हें जानते हैं, का वित्तपोषण। 2011-12 में इस क्षेत्र ने विनिर्मित उत्पादों के महत्वपूर्ण हिस्से को निर्मित किया जो सकल घरेलू उत्पाद के 12 प्रतिशत से अधिक था। उनके प्रबल निर्यातोन्मुख होने के अलावा उनमें रोजगार की भी मजबूत क्षमता निहित है जो लगभग 100 मिलियन लोगों को रोजी-रोटी उपलब्ध करा रहा है, जो शायद कृषि क्षेत्र से ही कम है। उनमें से अधिकांश के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित होने के कारण ये ग्रामीण विकास का बेहतरीन अवसर भी प्रदान करते हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र से उनके आगे के और पीछे के संपर्कको देखते हुए मैं उनको विकास के 'मौन' इंजन, विशेषरूप से धीमे आर्थिक चक्रों में, के रूप में देखता हूँ।

24. बहुत से अध्ययनों का यह परिणाम रहा है कि प्रतिष्ठा तथा मूर्त संपार्श्विकों की कमी के कारण इन संस्थाओं के बाहरी निधीयन के लिए कर्ज के माध्यम से वित्तपोषण, जो मुख्यतः अनौपचारिक स्रोतों से लिया जाता है, प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। बैंकों के अक्सर दुर्बल होने वाले प्रलेखीकरण (डॉक्यूमेंटेशन) की अपेक्षाओं को देखते हुए जब बैंक से वित्तपोषण की बात आती है तो ये संस्थाएं अनुचित व्यवहार की शिकार होती हैं। एमएसएमई की चौथी जनगणना में यह पता चला कि सिर्फ 5.2 प्रतिशत इकाइयों (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत -दोनों) ने ही संस्थागत स्रोतों से वित्तपोषण प्राप्त किया है। अधिकांश इकाइयों, वास्तव में उनमें से 93 प्रतिशत, को कोई वित्तपोषण प्राप्त नहीं हुआ या वे स्व-वित्तपोषण पर निर्भर रहें। 2011 में हुए विश्व बैंक के उद्यम सर्वेक्षण में भी इन निष्कर्षों की पुष्टि की गई। बहस का मुद्दा यह है कि संस्थागत स्रोतों से एमएसएमई को होने वाला ऋण प्रवाह उनके द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों के समानुपातिक नहीं है।

25. 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक के चर्चा पत्र में बैंकों और निजी इक्विटी के एक नवोन्मेषी संयोग प्रस्तुत किया गया है जिसमें ऋण उपलब्धता की इस बाधा को दूर करने के उपाय के रूप में ऋण में वृद्धि की प्रणाली/उपाय के रूप में राज्य की संभावनायुक्त भूमिका को दर्शाया गया है। इसमें यह प्रस्ताव भी किया गया है कि इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में छोटे बैंक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरणार्थ - रिलेशनशिप बैंकिंग।

26. बैंकों की ओर से एक शिकायत अक्सर सुनी जाती है कि जब बकाया चुकाने की बात आती है तो एमएसएमई अक्सर चिंताकुल हो जाती हैं। इस बात को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है एमएसएमई अक्सर बड़े उद्योगों की सहायक के रूप में कार्य करती हैं और उनका नगदी प्रवाह असमान (ढेलेदार) होता है। विशाल उद्योगों का कारोबारी अभिविन्यास अक्सर एमएसएमई को प्रत्यक्षरूप से प्रभावित करता है। परिणामस्वरूप एमएसएमई इकाइयों की निधियों के पुनर्चक्रण तथा कारोबारी परिचालनों को नुकसान पहुंचाते हैं। निधि स्वीकृत करने के समय बैंकों को सुरक्षात्मक रख अपनाते हुए एमएसएमई यूनिटों से संबंधों का

सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इन संस्थाओं से संबंधित विलंबित भुगतान ब्याज अधिनियम, 1998 के वर्तमान प्रावधानों में समुचित संशोधन किया गया है जिसमें उनकी विशिष्टताओं का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा, बैंकों को सलाह दी गई है कि एमएसएमई क्षेत्र से खरीद के संबंध में भुगतान देनदारियों को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को स्वीकृत समग्र सीमाओं के अंतर्गत अलग से उप-सीमाएं निर्धारित करें। संसद ने फैक्ट्रिंग रेग्यूलेशन बिल पारित किया है जिससे लघु और मध्यम उद्यमों की भुगतान में विलंब तथा चलनिधि संबंधी समस्याओं के समाधान होने की संभावना है। मुझे यकीन है कि इन उपायों से इस क्षेत्र को बीमार करने वाली बाधाओं को काफी हद तक दूर करने में सहायता मिलेगी।

संसाधन जुटाना

27. जैसा कि हमने देखा, देश के विकास के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। हम संसाधन कैसे जुटाएं ? यहां पर लोगों की बचत जुटाने में बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है। मार्च 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने ₹76 ट्रिलियन की राशि एकत्र की है। देश में वर्तमान में 146 अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) हैं जिनकी 1.2 लाख से अधिक शाखाएं इस गतिविधि में लगी हुई हैं। हालांकि, आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए हमें और अधिक लोगों तक पहुंच बनाने की आवश्यकता है और इसलिए भारत में अधिक बैंकों के कामकाज करने की आवश्यकता है। हमें न सिर्फ अधिक बैंक बल्कि शायद विभिन्न प्रकार के बैंकों की आवश्यकता है। मैं यहां पर सरकारी, निजी या विदेशी बैंकों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां बैंकों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कामों की बात कर रहा हूं, उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं जिसमें बैंक उत्कृष्ट होना चाहते हों। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने और अधिक बैंकों को लायसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया है। हाल ही में दो लायसेंस प्रदान किए गए हैं। हमारी मंशा मांग के आधार पर लायसेंस प्रदान करने की है। हम पूर्ण सेवा प्रदान करने वाले वाणिज्य बैंकों तथा पृथकरूप से लायसेंस जारी किए गए बैंकों -दोनों के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने की तैयारी कर रहे

हैं। हम आशा करते हैं कि अधिक बैंक होने से बैंकिंग क्षेत्र अधिक तेज गति से आर्थिक वृद्धि के लिए अधिक संसाधन जुटाएगा, वित्तीय समावेशन लाएगा तथा उस माध्यम से संवहनीय तरीके से समवेशी विकास को सहारा प्रदान करेगा।

उपसंहार

28. मैंने समसामयिक दृष्टि से प्रासंगिक और जिनके निकट भविष्य में काफी समय तक महत्त्वपूर्ण बने रहने की संभावना वाले बहुत से मुद्दों पर थोड़ी चर्चा की है। इस तरह के सम्मेलन संरचित

तथा व्यवस्थित ढंग से विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं, साथ ही इनमें क्षेत्र विशेष की चिंताओं पर भी विचार भी किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आयोजक इस एकबारगी सम्मेलन के साथ नहीं रुकेंगे, बल्कि मुद्दों पर आगे चिंतन करने के लिए अनुगामी विचार-विमर्श भी आयोजित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विचार-विमर्श अपने तार्किक परिणामों तक पहुंचेंगे।

29. धन्यवाद।